Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 27-02-2006
Participants : Atwal Shri Charnjit Singh

an>

Title : Deputy Speaker made reference to passing away of Shri Janardan Jagannath Shinkre, member, 4th Lok Sabha on 24 December, 2005.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Janardan Jagannath Shinkre.

Shri Janardan Jagannath Shinkre was a Member of the Fourth Lok Sabha from 1967 to 1970, representing Panjim Parliamentary Constituency of Goa, Daman and Diu.

Shri Shinkre took active part in Goa's freedom movement during 1946 to 1961.

Shri Shinkre was the Principal of Portuguese schools from 1939 to 1947 and was associated with the Gomantak Shikshan Sammelan and the Gomantak Sahitya Sammelan.

A man of letters, Shri Shinkre edited 'Yugantar' a Marathi magazine and 'Deepgriha', a Marathi weekly. He has to his credit Marathi novels, namely, 'Madhli Bhint'; 'Bhiti'"; 'Sanshayatme: Collection of Jokes' and 'Kamra No. 9'. He was the editor and proprietor of the Marathi daily, *Pradeep*.

Shri Janardan Jagannath Shinkre passed away on 24 December, 2005 at the age of 89.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House would join me in conveying our condolence to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.02 hrs.

-

The Members then stood in silence for a short while.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज सदन में चर्चा की जानी चाहिए…(व्यवधान) किस तरह से ज्यूडिशियरी को प्रभावित किया जा रहा है, उसे खरीदा और बेचा जा रहा है।…(व्यवधान) पूरे हिन्दुस्तान में नंगा नाच हो रहा है।…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the proper way.

…(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक : हमारे कुछ सदस्यों को इस सदन से निकाल दिया गया, लेकिन आज ज्यूडिशियरी को खरीदा और बेचा जा रहा है।…(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : फोन टैपिंग का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस मामले में सरकार से बयान मांगते हैं। …(व्यवधान) हम इसमें मिनिस्टर साहब से बयान मांगते हैं।…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the proper way.

स्वी ब्रजेश पाठक : उपाध्यक्ष जी, किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यूडिशियरी को खरीदा और बेचा जा रहा है।…(व्यवधान) इस पर आज सदन में गंभीरता से चर्चा कराने की आवश्यकता है।…(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, फोन टैपिंग के मामले पर हम सरकार से बयान मांगते हैं।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे हाउस को चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेजीडेंट बुश की आगामी भारत यात्रा के बारे में हमने आपसे अनुरोध किया है।...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक : उपाध्यक्ष जी, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर ज्यूडिशियरी को किस तरह से खरीदा और बेचा जा रहा है, इस पर आज सदन में चर्चा करायी जानी चाहिए।...(व्यवधान) इससे बड़ा सवाल कोई दूसरा नहीं हो सकता।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे हम ज़ीरो ऑवर में लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक : नहीं, ज़ीरो ऑवर में नहीं। सर, अभी मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। हम अपनी बैंत सदन के सामने रखना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है।...(व्यवधान) आपसे अनुरोध है कि इस विाय पर आज सदन में चर्चा कराने का कट करें।...(व्यवधान) अखबारों की प्रतियों में साफ आया है कि किस तरह से ज्यूडिशियरी को खरीदा और बेचा जा रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Please do not show the paper.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not show the paper. This will not go on record. Now, why are you wasting the time?

(Interruptions) ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot allow this. Do not show the paper and nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जीरो ऑवर में अपनी बैंत कहना।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot allow this.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Mr. Brajesh Pathak, nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

12.□ Not Recorded

उपाध्यक्ष महोदय : पाठक जी, अभी आपकी कोई बैंत रिकार्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि जीरो ऑवर में आपकी बैंत मानेंगे और सुनेंगे भी।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है कि आपकी इच्छा जीरो ऑवर में बोलने की नहीं है।

…(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Madhusudan Mistry, have I invited you to say like this? Please sit down.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिकी राट्रपति बुश के भारत आने के पहले जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में सरकार ने जो गोलमेज कांप्रड्डेंस बुलाई थी...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, this is not a matter of urgent public importance. ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो ऑवर में अलाऊ करूंगा। प्रश्न काल के बाद जीरो ऑवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : This is Question Hour. That is not a matter of urgent public importance. It can be taken up during 'Zero Hour'. ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं आया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह देशद्रोह की बैंत है। इस तरह से आप जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की बैंत कर रहे हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बैंत जीरो ऑवर में सुनेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : It can be taken up during 'Zero Hour'. This is not a matter of urgent public importance. ... (*Interruptions*)

श्री ब्रजेश पाठक : यह तय है कि आप जीरो ऑवर में हमें समय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जितना समय जीरो ऑवर में आपको मिलता, उससे ज्यादा समय तो आपने अभी ले लिया है। वैसे भी आपने इस सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री ब्रजेश पाठक : नोटिस दिया है। आप स्वीकार कर लें कि हमें जीरो ऑवर में समय देंगे। जैसे आपने इन्हें आश वासन दिया है कि जीरो ऑवर में मौका देंगे, हमें भी अपनी बैंत रखने का आश्वासन दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. I will see at that time. If your notice has come, I will try to accommodate you.

स्वी ब्रजेश पाठक : हमने नोटिस दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have told you that I will try my best to accommodate you.

11.08 hrs

MR SPEAKER: Shri Sanjay Dhotre,Q. No. 122.

स्वी संजय धोत्रे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महाराट्र की सिंचाई परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा था कि क्या केन्द्र के शेयर की वजह से कोई योजना रुकी हुई है? उसके जवाब में बताया गया है कि यह विाय राज्य सरकार का है, लेकिन पिद्वले साल केन्द्र द्वारा महाराट्र को जो 707 करोड़ रुपए की धनराशि मिलनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट 529 करोड़ रुपए ही मिले हैं, इसलिए यह जवाब सही नहीं है। क्या केन्द्र सरकार इस साल महाराट्र के इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने के लिए कुछ और धनराशि मुहैया करÉAMÉÉÒ[R1]?

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : इससे पहले कि मैं इनके सवाल पर आऊं, थोड़ी जानकारी सदन को होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शायद इसमें कुछ एडीशन करना चाहते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं इनके सवाल का साफ जवाब दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि कल्चरेबल कमांड एरिया में 10 हजार हैक्टेयर से ज्यादा एरिया के मेज़र प्रोजैक्ट्स होते हैं, उसके बाद मीडियम प्रोजैक्ट्स दो हजार हैक्टेयर से दस हजार हैक्टेयर तक के होते हैं और उसके बाद माइनर प्रोजैक्ट्स होते हैं जो दो हजार हैक्टेयर से कम एरिया के होते हैं। ये सारे प्रोजैक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अपने होते हैं। हमारे मंत्रालय में जो टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी है, वह उनकी जांच करती है और उसके बाद परमीशन देती है। कई रियासतों में अन-अप्रूव्ड प्रोजैक्ट्स भी

चैंलते हैं जबकि अप्रूव्ल जरुरी है, लेकिन फाइनेंस का इन प्रोजैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। इन्होंने महाराट्र के बारे में जो सवाल उठाया है, इनकी जानकारी सही नहीं है कि वहां सैंत सौ करोड़ रुपया मिला है। हमारे मंत्रालय में जो सूचना है उसके अनुसार एआईबीपी के दायरे में 151 प्रोजैक्ट्स महाराट्र के हैं, जिनमें से 57 अप्रूव्ड हैं और 94 अन-अप्रूव्ड हैं। किसी वक्त सदन में बैंत उठ सकती है कि यह अनअप्रूव्ड क्या चीज है। पहले कुछ गैलतफहमी पैदा हो गयी थी लेकिन जो एआईबीपी में प्रोजैक्ट्स हैं, जिनका कंसर्न डायरेक्टली मेरी मिनिस्ट्री से है, उसमें महाराट्र के लैलए 30 प्रोजैक्ट्स सैंक्शन्ड हैं। इनके ऐसे 11 प्रोजैक्ट्स में से 8 प्रोजैक्ट्स फास्ट ट्रैक में लिये गये हैं। फास्ट ट्रैक में वे प्रोजैक्ट्स अैंते हैं, जिनको दो र्वा में कम्प्लीशन के लैलए केन्द्र सरकार कोशिश करती है। मुझे खुशी है कि महाराट्र को इंसाफ मिला है। Not as a special case, but because Maharashtra is a State which is performing better. उनको पहले 80 और 20 की रेशो में धनराशि मिली है, जिनमें लोन पूरा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 80 प्रतिशत भाग देती थी। उसके बाद महाराट्र सरकार को फास्ट ट्रैक प्रोजैक्ट्स हेतु 100 प्रतिशत राशि मिली है। हमारे मंत्रालय की सिफारिश पर लोन का पूरा कम्पोनेंट ग्रांट के साथ जुड गया है। इसलिए लोन कंपोनेंट और ग्रांट कंपोनेंट दोनों को मिलाकर महाराट्र सरकार को 1199 करोड़ रुपये मिले हैं।

Not as a special case, but because Maharashtra is a State – which is performing better.

स्वी संजय धोत्रे : आपके यहां से कुछ स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स को ही विशेा अनुदान लैमलता है या स्टेट गवर्नमेंट को आप जो राशि देते हैं, अलग-अलग प्रोजैक्ट्स पर जो खर्चा होता है, क्या उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है या आपके यहां से धन जाता है।

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : यह प्रोजैक्ट सेंट्रिक होता है। मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार की सिफारिश होती है, वह अपनी जांच करती है और पूरी जांच करने के बाद हमें प्रोजैक्ट्स भेजती है और उन प्रोजैक्ट्स पर हम राशि देते हैं। आपके जो 30 प्रोजैक्ट्स हैं उनमें से कई कम्प्लीट हो गये हैं, जो मैं अभी आपको बता सकता हूं। दूसरे प्र ोजैक्ट्स अभी चैनल में हैं। इसलिए हमारे यहां जो प्रोजैक्ट्स अैंते हैं वे महाराट्र सरकार की सिफारिश से, उनकी जांच के बाद और उनकी कोशिश से अैंते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स के विाय में आपका कोई खास सवाल हो तो बताइये[r2]?

SHRI G. KARUNAKARA REDDY : Sir, according to the latest information available, there are 19 incomplete major irrigation projects, 23 on-going medium irrigation projects and 28 Extension, Renovation and Modernisation (ERM) projects in Karnataka. Till before last year, the Union Government has given the assistance as 30 per cent grant and 70 per cent loan for these irrigation projects. But last year, the Union Government has stopped giving the loan and released the grant amount only and asked

the State Government to raise the funds on their own. Because of this stoppage of loan amount, the Government of Karnataka is facing great difficulty in completing these irrigation projects.

Sir, the hon. Prime Minister had announced recently that one crore hectares of land is to be irrigated in the country under Bharat Nirman programme and asked the State Government to furnish the details to be included under this programme. The Government of Karnataka has submitted a cost of project proposal for major, medium and ERM irrigation projects of Rs. 7,849.28 crore to be included in Bharat Nirman programme. If these projects in Karnataka are completed early, it will give great boost to the people of Karnataka in general and the farmers in particular who are the backbone of the country.

Sir, I want to know whether the Union Government is considering to re-introduce the proposal of 70 per cent loan assistance to the State of Karnataka which was given up to 2005. In his reply, the hon. Minister has stated that he is giving both grant and assistance to the Government of Maharashtra. I would like to ask the hon. Minister whether it is possible to introduce the same proposal for Karnataka also and if so by what time a final decision in this regard will be taken. I also want to know whether the Union Government is considering the proposal which is submitted by the Government of Karnataka under Bharat Nirman programme.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Sir, I feel very happy to refer to Bharat Nirman. Hon. Member has made a reference to that. Bharat Nirman certainly is a situation of hope for the country. But, when I was referring to Maharashtra, I just mentioned that it was performing well. Earlier, in the loan assistance, we had 80:20 ratio and then it became 100 per cent. But now, for the entire country, for general run-off States it is 70 per cent loan and 30 per cent grant. Yes, that grant is also available to Karnataka.

Sir, the hon. Member mentioned about Bharat Nirman. Under Bharat Nirman the situation is that one crore hectares of land will be cultivated and every State will get a share on the basis of justice and equity. There is no question of taking sides. I can assure this august House that my Ministry will be totally transparent.

SHRI G. KARUNAKARA REDDY : Thank you, sir.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : That ratio is available to everybody, especially to hilly States, rganizeed States like the North-East, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and some areas in Orissa where the grant will be 90 per cent and loan will be 10 per cent. You have referred to Bharat Nirman. It is a matter of joy and earlier the Chairperson of the UPA told the entire country about learning the problems of the farmers.

The hon. Prime Minister particularly went, among other places, to Andhra Pradesh to understand why the farmers are committing suicides. He went to the families of those in Somayajulapalli village, 30 kilometres from Kurnool. This was the background that Bharat Nirman came into focus. Under the Bharat Nirman programme it is possible to do justice to all areas, particularly the backward areas. But there is a situation which this august House may kindly consider. Under Bharat Nirman we shall have one crore hectares of land to be irrigated. It is a revolutionary step. But already demands have been received by my Ministry where they want to cultivate and irrigate two crore hectares of land. That is not possible. We have to cut our coat according to our cloth. It will be one crore hectares of land that will be brought under Bharat Nirman and States will have to discuss with us so that we are in a situation to do justice and equity[krr3].

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Balashowry Vallabhaneni.

SHRI G. KARUNAKARA REDDY : Sir, my question was whether the Union Government is considering to reintroduce giving 70 per cent loan to the State of Karnataka. He has not replied to that. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदयः आपका सप्लीमैंटरी हो गया है।

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, 70 per cent loan and 30 per cent grant is available. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदयः मैडम, आप बैठिए। आप पहले नोटिस भेजिए, तब देखेंगे। वह आपकी पार्टी के बोलने वाले मैम्बर हैं।

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Sir, Andhra Pradesh has a total of 40 rivers which have the capacity of 2,765 tmc while the water used for irrigation purpose every year is only 1,700 tmc. Apart from this, every year 3,000 tmc water from the Godavari is going waste, into the sea, which we are not able to use. On the other side, farmers of Andhra Pradesh have committed suicides because of continuous droughts. To come out of this tragedy, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Rajasekhara Reddy, has started a unique programme called *Jalayagnam* which is to make full use of surplus water which is now going into the sea.

Andhra Pradesh Government has already started 30 major and 18 minor irrigation projects at the cost of Rs. 46,000 crore to irrigate 73 lakh acres of land. Apart from this, they are going for stablisation of 20 lakh acres of land.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your supplementary.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : For completion of these projects, the Government of Andhra Pradesh has allocated Rs. 10,000 crore which is 51 per cent of its total Plan Budget for the current year, which is the highest in the country. I would like to ask the Minister when the Government of Andhra Pradesh is making such big steps to help the farmers in the State, whether the Central Government would extend the help sought by the Government of Andhra Pradesh, that is, Rs. 8,000 crore every year till completion of the above projects.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Hon. Member Shri Balashowry has raised a very important question, but it is a situation to be tackled by the Andhra Pradesh Government within its own resources there. Andhra Pradesh Government committing 51 per cent of the Plan Budget for 48 projects is a laudable thing. I appreciate that. But whatever is possible to be done within the AIBP, within this Ministry, I will certainly respond to that. Whatever money you require, you have to project it in the Plan discussions with the Planning Commission and the Ministry of Finance, but under AIBP, we shall certainly respond to your demands.

As for our approval to the major and medium projects, we shall examine them and TAC will sit or we shall rganize a discussion. They will examine and support you wherever it is needed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Soz Saheb, you are also requested to address the Chair and not the individual. That will create a trouble for you.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there has been a stagnation in regard to extension of irrigation in our country as there has not been sufficient allocation for irrigation. There is a need for enhancement of allocation for irrigation.

There is one important project in North Bengal, Tiesta Irrigation Project. So far, the Central Government has not provided sufficient funds for that project. If that project is completed, life of the entire North Bengal will change. That is very necessary for four districts of North Bengal. I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government will provide sufficient funds to complete Tiesta Irrigation Project expeditiously.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, Shri Basu Deb Acharia's question is in two parts. First, he has raised the question of loan and grant dwindling for irrigation project. I have no hesitation in saying that we have to do something so far as allocations for irrigation are concerned[reporter4].

Irrigation should receive very great importance, but Bharat Nirman has already responded to it.

As regards Tiesta Irrigation Project, it has been recommended to the Planning Commission, and it is receiving attention.

As regards your query about your projects, a component of the grant of Rs. 170 crore have already been allocated by way of grant, but the loan component is always there. The Planning Commission is considering about the Tiesta Project.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my colleague Shri Balashowry from Andhra Pradesh has already admitted here that farmers from Andhra Pradesh are committing suicide, and it is a fact.

Sir, the Maharashtra Government has been utilising the water according to the Godavari Water Tribunal agreement. Meanwhile, they are constructing one project called the Babli Project without the knowledge of the Government of Andhra Pradesh, and violating the inter-State agreement.

Is it a fact that the present Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Rajasekhara Reddy has written to the then Minister of Water Resources, Government of India Shri Priya Ranjan Dasmunsi on this issue? Did Shri Dasmunsi, after receiving the letter, give instructions to the Maharashtra Government not to proceed with the Babli project as this was against the inter-State agreement? I would like to mention that even now the work is going on with regard to this project. What action has the Government of India taken so far on this issue? I want to know about this matter from the hon. Minister, as this is a very important issue. A lot of agitations are also going on in the Adilabad District. Therefore, I would request the hon. Minister to respond on this very important issue.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, it is outside the matrix of this Question. Therefore, it cannot be readily answered. I will look into this matter, but you kindly raise this Question separately.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, the Babli Project is a very important issue.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, it needs a separate Question. Hon. Member, you can come with a separate Question, and I will respond to it. But it cannot be answered like this. I am not a judge. I have to listen to the demands of the States also.

Hon. Member, please give a separate notice, and I will look into it. Otherwise, I invite you to discuss it with me personally.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, I am humbly requesting, through you, to the hon. Minister to go through the Chief Minister's letter, and I would request him to please take initiative in the interest of the farmers of Andhra Pradesh. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please give a separate notice on this issue.

… (*Interruptions*)

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Sir, I will look into it.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, this issue is very much concerned with the State of Andhra Pradesh. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI E. PONNUSWAMY : Sir, they are violating the law. … (*Interruptions*)

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Sir, it is a very relevant Question relating to Godavari river. It seems that the hon. Minister has not done his homework properly. … (*Interruptions*)

SHRI P. MOHAN : Sir, it is a very important issue concerning Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Now, nothing is going to be recorded.

(Interruptions) ...*

श्री रामदास आठवले : महाराट्र में इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है और आपने इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महाराट्र सरकार ने जब इतना अच्छा काम किया है, तो क्या आप महाराट्र को ज्यादा पैसा देने के लिए सोच रहे हैं? ह्महाराट्र में कृष्णा नदी का पानी रोकने के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन पैसा कम पड़ रहा है इसलिए भारत सरकार को कृष्णा नदी का पानी रोकने के काम में भी मदद करनी चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि मुम्बई और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश होती है। उस पानी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को वहां एक टीम भेजकर सर्वे कराने की आवश्यकता है। अगर उस पानी को रोका जा सके तो इससे महाराट्र के कई जिलों को पानी मिल सकता है। मुम्बई और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश होती है। अगर समुद्र में जाने वाले पानी को रोककर, जहां कम पानी है, वहां ले जाने के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो इससे हमारी मदद हो सकती है। इस बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है?

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : जहां तक पैसे की बैंत है, मेरे खयाल से पैसे की दिक्कत नहीं है। मेरे चार्ट में दिया गया है कि जिन प्रांतों को पैसा दिया गया है, वे उसे पूरा खर्च भी नहीं कर पाए हैं। अगर महाराट्र की ओर से डिमांड आती है तो उसे हम देखेंगे और उसकी जांच करेंगे, पी.ए.सी. में भी डिसकस करेंगे और इसके लिए प्लानिंग कमीशन से भी बैंत हो सकती है।

---

12. Not Recorded.

जहां तक मुम्बई और कोंकण इलाके में बारिश के पानी की बैंत है, I want to share this thinking with the august House that this Ministry will raise a very vigorous movement for the purpose of rain-water harvesting[ak5].

In fact, we should tell the countrymen and women that not a drop of rainwater should be wasted. Therefore, this is already under my attention. मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मैं भारत की शक्ति देखता हूं। मैं सिर्फ मंत्रालय में नहीं देखता हूं, बाहर जो लोग काम करते हैं, मैं उन्हें भी देखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में मैगासासे अवार्ड किसलिए मिला - क्योंकि उन्होंने एक सिचुएशन पैदा की और बारिश का पानी जमा किया। पुणे में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए मैं उन विद्वान लोगों की एक लिस्ट बना रहा हूं, जो बारिश के पानी को बचाना चाहते हैं, ताकि इर्रिगेशन का काम अच्छा हो सके। चूंकि आपने यह मैटर रेज किया है, इसलिए मैं कोंकण की तरफ तवज्जह दूंगा।

I want to share this thinking with the august House that this Ministry will raise a very vigorous movement for the prupose of rain-water harvesting. In fact, we should tell the countrymen and women that not a drop of rainwater should be wasted. Therefore, this is already under my attention.

स्वी रघुनाथ झा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के कितने प्रोजैक्ट्स आपके यहां वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं। आपको मालूम है या नहीं कि गंगा एक अंतर्राट्रीय नदी है और इसमें आने वाली बाढ़ से प्रति वर्ा बिहार के हजारों गांव कट जाते हैं और खेती बरबाद हो जाती है। दस लाख हैक्टेयर में हमारे यहां वाटर लॉगिंग की प्राब्लम है तथा सिंचाई की प्रॉब्लम है। गंडक, बागमती, कोसी और अदवारा समूह की सारी योजनाएं आपके यहां आकर पड़ी हुई हैं। मंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और आप अभी कागज पढ़ रहे हैं। आप इस संबंध में कौन सा पड्डैसला लेना चाहते हैं और बिहार के इन सारे प्रोजैक्ट्स को कब तक रिलीज करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार का पड्डैसला ही वह कागजों में ढूंढ रहे हैं।

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : बिहार की सारी प्रोजैक्ट्स का ब्यौरा इस वक्त देना और आपके साथ डिस्कस करना नामुमकिन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के बारे में आपने जो चिंता व्यक्त की है...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : एक पर्टीकुलर स्टेट महाराट्र के बारे में यह प्रश्न है, आपने बिहार और बाकी सारी स्टेट्स का अध्ययन उत्तर देने के पहले क्यों नहीं किया, नहीं तो इसे पोस्टपोन कर दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to him.

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : बिहार की चिंता आपको करनी चाहिए क्योंकि आप वहीं से चुनकर आये हैं, लेकिन बिहार के क्या प्रोजैक्ट्स हैं, इस बारे में आप मेरे मंत्रालय में आइये और डिस्कस कीजिए, जो भी करना होगा, वह कर लेंगे। यदि आपको यह ब्यौरा चाहिए कि बिहार को कुछ मिला या नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार को कितनी ग्रांट्स मिली हैं।

श्री रघुनाथ झा : आप कब तक उन्हें पूरा करायेंगे, इस बारे में आश्वासन दीजिए। बिहार के हम सारे एम.पीज. आपसे आकर मिलेंगे।

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : ठीक है, आप आ जाइये, हम डिस्कस करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : झा साहब, आप बैठिये।

(Q. No. 123)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, two studies have been done in 2003-04 by ORG-MARG, which show that in the North-Eastern States, diversion of wheat is 100 per cent, and for other States, it is 53.3 per cent in case of wheat, and 39 per cent in case of rice. One more study done by the Planning Commission says that

food grains leakage through ghost cards is 16.67 per cent and food grains leakage at FPS is 19.71 per cent. … (*Interruptions*)

SHRI K.S. RAO: It is very alarming.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: As regards kerosene, a study conducted by the National Council of Applied and Economic Research says that 38.6 per cent diversion has taken place. Will the hon. Minister be kind enough to say what has been the loss to the Central Government? I would like to know what has been the monetary loss to the Central Government.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप नुकसान के बारे में बतायें।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTIION(SHRI SHARAD PAWAR) : It will be difficult to give the figures or the amount. But it is true that it is a very serious issue. Both reports brought to the notice of the Government that there is a substantial diversion, especially in the North-East. When we got the reports, we immediately sent copies to all the States and we have requested the State Governments that they should give their comments. Along with my colleague, the Minister of State, I myself had gone to the North-East and called a meeting of the representatives of the North-East, including the Chief Minister of Assam. We have raised this issue before them. We are taking all precautions to curb this[R6].

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I have not got the correct answer to my first question regarding the monetary loss suffered by the Government.

The Programme Evaluation Study by the Planning Commission had given certain recommendations. It was recommended that they should do away with the methodology of identifying the poor families on the basis of income-expenditure criteria. The organisation has also asked the Planning Commission to devise an appropriate criterion and method of BPL identification that would enable the States to limit the size of the target group and the neighbourhood. Is the Government going to

consider the suggestions given by the Programme Evaluation Study and implement them?

I would like to reiterate my first specific question. What has been the monetary loss suffered by the Government?

SHRI SHARAD PAWAR: About the monetary loss, I said that I have to collect the figures and I have no hesitation in giving them.

उपाध्यक्ष महोदय : यह करना मुश्किल है।

श्री शरद पवार : हम जो दे सकते हैं, वह देने का बंदोवस्त भी करेंगे।

Simultaneously, about the recommendations that have been communicated, we have already sent them to the States. Implementation of the Public Distribution System is a responsibility of the States. We have communicated to the State Governments the recommendation given in that report. We are going to take it seriously and we are going to call a meeting of all the States also.

I have now got the figures asked for. During the year 2003-04, the total amount spent was Rs.7,258 crore, in sixteen States. Out of that, Rs.4,197 crore did not reach the BPL card holders or households. So, practically more than 55 per cent of the amount has not reached the BPL households.

SHRI K.S. RAO : Even the subsidy amount?

SHRI SHARAD PAWAR: This is a subsidy amount.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, the matter of diversion of PDS food grains is very serious. I have very carefully noted the answer given by the hon. Minister. I wish to bring to his notice an instance where nearly 13,800 quintals of food grains did not reach the targeted group in one Panchayat only of my constituency and this was for as many as eight continuous months. Till date we do not know where that quantity had gone. We have been asking the State Government to let us know. Anyway, that is a different matter.

Such reports of diversion are very widespread. Wherever the price of food grains in the open market rises above the above-poverty-line price, such off-take takes place. To my understanding, the FCI is not interested in preventing such diversions. Would

the Government consider directly subsidising the target groups and then raising the price of food grains in the Fair Price Shops to that of the open market price so that this diversion is prevented? It is a policy decision.

SHRI SHARAD PAWAR: I do not think it is possible to provide money directly. We have to see that the subsidised food grains which have been allotted to the States, reach the poor man. If you study this entire diversion minutely, a substantial diversion is from the above-poverty-line (APL) people. There are many States which are transferring this wheat to the flourmill-*wallahs* who are converting that wheat into *atta* and selling it in the open market. In fact, there was a request from the North-Eastern States that we should continue with this policy. But we have recently put one condition. We have no objection to hand over this entire wheat to the flourmill-*wallahs* but that converted *atta* has to come to the Public Distribution System and it has to reach the people at reasonable price. We have put that condition[KMR7].

We are allowing the State from the North-East. But let me tell you frankly that we are going in detail. But I have my own doubts about some of the figures. There are two reports. One is from the ORG-MARG, which has given certain Reports; and there is a Sub-Committee report from the Planning Commission. Both these Reports are altogether different. There are certain States which are taking a lot of interests to execute this Public Distribution System efficiently. Take the cases of West Bengal, Andhra Pradesh and Kerala. It has been shown here that there is a substantial diversion in the case of West Bengal, which I myself is not ready to believe. I have to do in detail. Unless and until, we go into details and collect proper reactions from the respective State Governments, we do not want to reach to any conclusion.

SHRI TAPIR GAO : Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister this. The Minister has expressed full concern for the North-East. We are happy to know this. I have got a specific question. Since 1995, the Ministry has issued different orders to the North-East, especially to Arunachal Pradesh for Hill Transport Subsidy. In 2005, after a gap of ten years, the Ministry has issued an order to all these independent agencies, who are evaluating the Public Distribution System in the North-East, particularly Arunachal Pradesh, to go back to order.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your supplementary.

SHRI TAPIR GAO : With that calculation, the Ministry has found more than Rs.170 crore excess payment to Arunachal Pradesh. Now, the Public Distribution System is totally a failure in the North-East. Hence, I would like to know from the hon. Minister under what circumstances, the Ministry has issued order to calculate that ten-year back order. Thank you, Sir.

SHRI SHARAD PAWAR: This is also a very serious problem. Let me bring it to the notice of this august House that in Arunachal Pradesh, there are certain villages where you cannot send either truck or any other vehicles because of the geographical position. You have to take food grains on your head. It is called `headload'. The total bill of the `headload' was coming to Rs.10 to Rs.2 crore. Suddenly, it has jumped to Rs.400 crore. On seeing a jump from Rs.10 to Rs.20 crore to Rs.400 crore, I thought that it is our responsibility to go into the details as why such a huge jump has taken place. We found that there are a lot of *hera-pheri.* Hence, concerned officers were withdrawn. We have taken a number of actions there. We are taking legal action against many people. This looks like a *prima facie* report and it seems like a clear-cut cheating against the Government.

SHRI P. KARUNAKARAN : In the answer given by the hon. Minister, it is stated that in almost all the States, the food grains, such as rice and wheat, are diverted to some other purposes. Sir, it is understood that even at the distribution point, that is, from the FCI godowns itself, the agents or the contractors bring it to the open market. Has the State Government any such information to the Central Government in this regard? If yes, has any action been taken by the State Government or the Central Government in this case because it is nothing but looting the public money?

SHRI SHARAD PAWAR: I entirely agree with it. We have communicated to all the State Governments that this is the factual position of their States and we are waiting for their comments. We have not received any comments till yesterday. Some of the actions, which have been taken by some of the State Governments, have been given in the annexure. Practically, most of the State Governments have taken certain actions and some of the States have started taking correction action. Take the examples of Andhra Pradesh, Kerala, Chhattisgarh and Sikkim[R8].

*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN : Sir, The Tribune has published a report regarding PDS in its issue dated December 13. 2005. Its heading is…. "Punjab [p9]numero uno in PDS corruption". Punjab is the most corrupt State in the distribution of food grains through the Public Distribution System. In Punjab, as much as 76.50 per cent of total highly subsidized food grains meant for Below Poverty Line (BPL) families through Public Distribution System is diverted to the market. It is further mentioned that the depot holders divert subsidized food grains to the market in connivance with the local politicians and officials in the State Food and Supply Departments and other bureaucrats. Notably, in Punjab, only 10.50 per cent of the subsidized food is reaching the targeted BPL families through TPDS[p10].

---

12. English Translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Sir, I would like to know from the Hon. Minister regarding the action taken by him against bureaucrats who are responsible for the bungling in the PDS. What is the Government doing to ensure that the subsidized foodgrains reach the BPL families? I had raised this issue in the earlier session too. I had brought the situation in Punjab to the notice of the Hon. Minister. In the last few days, some trucks carrying PDS foodgrains elsewhere have been intercepted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put the supplementary.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN : what steps are being taken by the Hon. Minister against the corrupt officials? How will he ensure that the subsidized foodgrains under the PDS reach the BPL families?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What action has been taken against the State officials?

SHRI SHARAD PAWAR: The State Government is supposed to take action. We have brought it to the notice of the State Government. Whatever information we have got from the State Government between the period January 2004 and June 2004, the total action taken is as follows: Depots checked 16,550; Show-Cause Notices issued – 606; depots suspended – 284; depots cancelled 34; and depots fined 151. Secondly, as per the half yearly report on the action taken under clause 9 of the PDS (Control) Act, the action taken between January 2005 and June 2005, is as follows: Depots checked

16,145; Show-Cause Notices issued 881; depots suspended 204; depots cancelled 45; and depots fined 295. Definitely, certain action has been taken by the State Government. But this report about fifty per cent diversion itself is a serious thing. That is why, we are taking up with the Punjab Government. They have to take corrective action. … (*Interruptions*)

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, you are giving 45 minutes for two questions. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो पार्टी लीडर्स ने डिसाइड किया है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन रहे थे। यह बैंत सही है कि उ पभोक्ताओं को सामान की आपूर्ति केन्द्र सरकार करती है लेकिन उसके वितरण की व्यवस्था और निगरानी करना राज्य सरकार का काम है। आज कुछ देहाती इलाकों में परेशानियां हैं। जिनका पहले से राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन परिवार के विस्तार के कारण, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण, आबादी बढ़ने के कारण, देहाती इलाकों में परिवारों का बँटवारा होता रहता है, जिससे कुछ लोगों के नाम तो राशन कार्ड में हैं लेकिन परि वार के बँटवारे के कारण कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड में नहीं हैं। जो डिमांड राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को आती है, जिनके नाम राशन कार्ड पर चिह्नित हैं, यहां से उनके लिए ही सामान की आपूर्ति होती है। इसमें कैरोसीन तेल का ब्यौरा भी दिया गया है[h11]। हालांकि यह मामला पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कृषि मंत्री जी ने यहां उत्तर दिया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहार से केरोसिन तेल की क्या डिमांड है और कितनी आपूर्ति होती है? क्या डिमांड के अनुसार आप आपूर्ति करेंगे?

दूसरा प्रश्न यह है कि जिन परिवारों का बंटवारा देहाती इलाकों में हो जाता है, ऐसे लोग राशन कार्ड में नाम न होने के कारण, पीडीएस का सामान लेने से वंचित रह जाते हैं, क्या इस बारे में मंत्री जी तत्काल राज्य सरकार को निर्देश देना चाहेंगे कि उनके नये सिरे से राशन कार्ड बना कर, जो लोग वंचित हैं, उन उपभोक्ताओं को भी सामान मुहैया कराया जाए ? क्या आप इसका कोई रास्ता निकालेंगे?

श्री शरद पवार : जिस कमेटी ने इसकी जांच की है, उसने जो अनुशंसाएं की हैं, उनमें एक अनुशंसा यह है कि बीपीएल का राशन कार्ड जारी करने के लिए जिस तरह चयन किया जाता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है तथा राज्य सरकार को दोबारा बीपीएल की लिस्ट चैक करनी चाहिए और असली बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों का इसमें समावेश करने की आवश्यकता है। जहां तक केरोसिन की डिमांड का प्रश्न है, उसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Moreover, it does not come under the domain of this Question.

स्वी राम कृपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जबाब में इस बैंत को स्वीकार किया है कि इसमें लीकेज है और जो रिपोर्ट सब्मिट हुई है, उसमें भी ये बैंतें कही गई हैं कि तेल वितरण में लीकेज है, चीनी वितरण में लीकेज है, गेहूं और चावल के वितरण में भी लीकेज है। चीनी का तो अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसका आर्काणा लोगों में ख़ैत्म हो गया है। पहले सस्ती दरों पर आम लोगों को जो सामग्री मिलती थी, वह अब नहीं मिल रही है। खास तौर से यहां बीपीएल की चर्चा की गई है जिनके ैलिए बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से और खास तौर से एफसीआई के माध्यम से, गरीब तबके के लोगों तक सस्ता सामान पहुंचाने का संकल्प लिया है, निश्ंिचत तौर पर उसमें दोा है जिससे आम गरीब आदमी को सामान नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है, जो आपने स्टडी कराई है उसके अनुसार और व्यावहारिकता में यही बैंत सामने आई है कि ट्रक के ट्रक माल एफसीआई से सीधे मिलों में भेजे जा रहे हैं और सार्वजनिक ि वतरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक सामग्री आम गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन गड़बड़ियों को रोकने के ैलिए कौन सी ठोस कार्यवाही की गई है और जो एफसीआई के अधिकारी सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हैं, उनके विरुद्ध आपने कौन सी कार्यवाही की है? इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा सादृढ़ करने के ैलिए कौन-कौन से एक्शन आप लेने जा रहे हैं, ताकि यूपीए सरकार का जो संकल्प है कि आम गरीब आदमी को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराया जा सके, वह पूर्ण हो सके। इस बारे में आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं और इसे कैसे सादृढ़ करेंगे?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, this information has already been provided earlier.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Q. No. 124 : Shri Shishupal Patle – Not present;

Shri Ashok Kumar Rawat -- Not present.

(Q. No. 125)

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार समर्थन मूल्य घोाित करती है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जाती है। अधिकतर जगहों पर किसान को अपना माल छैंटे व्यापारियों को बेचना पड़ता है। छैंटे-छैंटे व्यापारी गांव में जाते हैं और वे सीधे किसान से समर्थन मूल्य से कम दाम पर माल खरीद लेते हैं।

किसानों का माल आपके सैंटर्स द्वारा सीधे न खरीद कर, छैंटे व्यापारियों का माल, जो उन्होने किसानों से समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदा है, आपके सैंटर्स द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है।

मैं माननीय कृाि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पिद्बले साल सरसों की फसल इतनी अधिक हुई, लेकिन आपके सरसों के सैंटर बंद हो गए, जिससे किसानों का माल खरीदा नहीं गया। आज भी लाखों टन माल मंडी में या किसानों के गोदाम में पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सप्लिमेंटरी क्वेश्चन पुट करें।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : माननीय मंत्री जी यह बताने का कट करें कि समर्थन मूल्य पर किसानों का जितना माल आपके सैंटर्स पर आएगा, क्या वह खरीदा जाएगा और उसके सैंटर बढ़ाने के ैलिए क्या कोई कार्य वाही की जाएगी[i12]?

ह्मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे सुनिश्च्िंत करेंगे कि किसानों के पूरे माल की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी और इसकी इन्फार्मेशन दी जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन्पङ्कर्मेशन कैसे देंगे ?

श्री शरद पवार : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरसों को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदने की बैंत है, मुझे पूरे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिद्बले साल, खासतौर से राजस्थान में और अन्य कुछ राज्यों में जहां सरसों का उत्त्पादन होता है, वहां सरसों की इतनी खरीद की गई थी जितनी पिद्बले 50 सालों में नहीं हुई थी।

महोदय, दो साल पहले ऑयल सीड्स की प्रोक्योरमेंट 300 करोड़ रुपए की हुई थी। पिद्बले साल सरसों की प्रोक्योरमेंट 3000 करोड़ रुपए की हुई थी। सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट करने का काम किया था और इसमें सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट राजस्थान में हुई थी।

यह बैंत साफ है कि जो प्रोक्योरमेंट राजस्थान से हुई, उसका ठीक तरह से मार्केट नहीं मिला और आज भी प्रोक्योरमेंट का 90 फीसदी माल गोदामों में भरा पड़ा है। वह किसानों का माल नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से नैपङ्केड ने खरीदा है और अब वह सरकार का माल है जिसे डिसपोज ऑफ करने के ैलिए हमने लिया है। वह डिसपोज ऑफ करना है।

महोदय, जहां तक इस साल की परिस्थिति है, मैं सदन के माध्यम से किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भले ही हमें पिद्बले साल नुकसान हुआ हो, मगर किसानों से पूरी सरसों खरीदने का काम हम जल्दी

से जल्दी शुरू करेंगे और जो कीमत सरकार ने तय की है, वह पूरी कीमत किसानों को देंगे, उनकी लूट नहीं होने देंगे। हम इस तरफ पूरा ध्यान देंगे।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, मैं उससे सहमत होते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था गांवों तक पहुंचे और जगह-जगह इसके सेंटर खुलें और किसान का माल पूरा खरीदा जाए। मैं उनसे यह भी आश्वासन चाहता हूं कि उन्होंने जो यहां कहा है, वह केवल आश्वासन बनकर न रह जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितना माल किसान लाएगा, वह इन सेंटरों पर खरीदा जाएगा और सरकार उनसे यह कह कर अलग नहीं हो जाएगी कि हमारे गोदामों में माल भरा पड़ा है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। सरकार धंधा करने के लिए नहीं बैठी है बल्कि सरकार समर्थन मूल्य इसलिए देना चाहती है, ताकि किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे यहां बताएं कि जितना माल इन सेंटरों पर आएगा, वह पूरा खरीदा जाएगा, उन्हें पूरी कीमत दी जाएगी तथा खरीद में कोई ढिलाई नहीं आने दी जाएगी ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has replied to that. There is no need for the Minister to reply to that.

SHRI K.S. RAO : While the prices of the manufactured goods and commercial items are being revised every 2-3 months with the result their prices are going up, the prices of the agricultural produce produced by the farmers are not going up at all. Even if there has to be some revision in the Minimum Support Price, it is only two per cent or five per cent every year because of which the gulf between the farmer and the urbanite is growing substantially high. A farmer having 25 acres of land is not able to educate his child in engineering or medical college, whereas a small employee is educating his child, whatever he wants.

I wish to know from the hon. Minister whether the policy and the guidelines in fixing the Minimum Support Price of farm produce will be totally changed so that they will be kept on par with the prices of commercial or manufactured goods. Otherwise, the purchasing power of the farmer or the rural poor who constitute about 65 per cent of the population of this country will affect the industry and the economy of our country also. So, I wish to know from the hon. Minister whether the whole policy of fixing Minimum Support Price of the agricultural produce will be totally changed. Will the hon. Minister undertake that exercise or not?

SHRI SHARAD PAWAR: There is a system. A separate independent Commission has been appointed who are supposed to go into the details of the cost of cultivation, what will be the remunerative price that should be given to the farmers, what is the total interest portion, what is the total investment, what are his own labour charges, etc. So, all these things will be carefully studied. It also consults the State Governments and gets information; it has some consultation with the Agricultural Universities and then comes to a conclusion.

If we say that every year, there is some improvement in the prices, one has to think as to what is the market change. For example, a question was raised here about *sarson*. Last year, *sarson* was purchased at Rs.1,700 and in the market, it was available for Rs.1,500. So, whatever *sarson* was purchased, we were not in a position to dispose it of. That situation is also there. Simultaneously we should not ignore the big network of the consumers; and his purchasing power has to be kept in mind.